भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 1976
गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

कोल्हापुर विमानपत्तन का विस्तार

1976. श्री शाहू शहाजी छत्रपतीः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोल्हापुर विमानपत्तन पर यात्री आवागमन, रनवे क्षमता तथा टर्मिनल अवसंरचना सहित उसकी वर्तमान परिचालन स्थिति क्या है;
(ख) क्या उक्त विमानपत्तन के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) उड़ान के अंतर्गत कोल्हापुर को मुंबई, पुणे और गोवा के अतिरिक्त हैदराबाद, दिल्ली तथा बेंगलुरु सहित अन्य शहरों से जोड़ने हेतु नए हवाई मार्गों को स्वीकृति देने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यात्रियों की बढ़ती संख्या और कार्यों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए बड़े विमानों के परिचालन तथा उड़ानों की संख्या में वृद्धि के लिए कोल्हापुर विमानपत्तन की अवसंरचना के उन्नयन हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): कोल्हापुर हवाईअड्डा एक कार्यशील हवाईअड्डा है। इसका रनवे कोड 3सी (एटीआर-72) प्रकार के विमान परिचालनों के लिए उपयुक्त है। इसके टर्मिनल भवन का बिल्ट-अप क्षेत्र 3,900 वर्ग मीटर है और यह व्यस्ततम समय में 500 यात्रियों और प्रति वर्ष 0.5 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान कर सकता है। कोल्हापुर हवाईअड्डे ने क्रमशः वर्ष 2023-24, वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के दौरान 1.60, 1.59 और 1.72 लाख यात्रियों को हैंडल किया है। हवाईअड्डों का विस्तार और विकास यात्री मांग, प्रचालन अपेक्षाओं और एयरलाइन की मांग के आधार पर किया जाता है। ऐसे विकास कार्य भूमि की उपलब्धता, वित्तीय व्यवहार्यता और प्रचालन संबंधी सरोकारों के अध्यधीन चरणबद्ध आधार पर किए जाते हैं।

(ग): वर्तमान में, कोल्हापुर हवाईअड्डे पर बेंगलुरु, हैदराबाद, नवी मुंबई और मुंबई के लिए अनुसूचित संपर्क उपलब्ध है। संशोधित 'उड़ान' योजना के तहत, कोल्हापुर को एक सेवित हवाईअड्डे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार, कोल्हापुर को जोड़ने वाले मार्ग बोली प्रक्रिया के आगामी चरणों के तहत बोली के लिए पात्र नहीं हैं।

(घ): हवाईअड्डा अवसंरचना का उन्नयन यातायात की मांग, प्रचालन संबंधी अपेक्षाएं, सांविधिक और अनिवार्य मंजूरियों की उपलब्धता, वित्तीय व्यवहार्यता और अन्य परियोजना-विशिष्ट अपेक्षाओं जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

******